

उल्फा के साथ शांति समझौते को समझना

द हिंदू

पेपर- III (आंतरिक सुरक्षा)

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने 29 दिसंबर, 2023 को केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के ज्ञापन में राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए कई खंड हैं और स्वदेशी समुदायों की भूमि और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन परेश बरुआ के नेतृत्व वाले वार्ता विरोधी गुट के रूप में एक चिंता बनी हुई है।

उल्फा का गठन कैसे हुआ?

उल्फा विदेशी-विरोधी असम आंदोलन का उप-उत्पाद है जो 1979 में शुरू हुआ और अगस्त 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। डर है कि असमिया और अन्य स्वदेशी समुदायों को उनके ही पिछवाड़े से बाहर कर दिया जाएगा। अवैध आप्रवासियों” (बांग्लादेश के लोगों) ने एक दिन आंदोलन शुरू कर दिया था। जबकि सामाजिक संगठनों और छात्र निकायों ने आंदोलन का रास्ता चुना, अरबिंद राजखोवा, अनुप चेतिया और परेश बरुआ सहित कट्टरपंथियों के एक समूह ने एक संप्रभु असम की स्थापना के उद्देश्य से सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए 7 अप्रैल, 1979 को उल्फा का गठन किया। . अपहरण और फाँसी की एक श्रृंखला शुरू करने से पहले समूह को म्यांमार, चीन और पाकिस्तान में अपने सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण में एक दशक लग गया। सरकार ने 1990 में ऑपरेशन बजरंग नाम से एक आक्रामक अभियान चलाया और उल्फा पर प्रतिबंध लगा दिया। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू करने के साथ असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

शांति प्रक्रिया कब शुरू हुई?

1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद विरोधी अभियानों के कारण 1,221 उल्फा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 1992 में, उल्फा सदस्यों के एक समूह ने आत्मसमर्पण करने और सरकार के साथ बातचीत करने का फैसला किया। सामूहिक रूप से, उन्हें स्थान या आत्मसमर्पित उल्फा के रूप में जाना जाने लगा, जिन्हें बाद में कथित तौर पर राज्य बलों द्वारा कट्टरपंथियों और उनके परिवारों के सदस्यों की पहचान करने और उन्हें निष्पादित करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे घुप्त हत्याएं के रूप में जाना जाने लगा। हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस जैसे आतंकवादी समूहों के समर्थन से, उल्फा कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश और भूटान में शिविर स्थापित किए। 2003 में भूटान के सैन्य हमले और 2009 में बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सत्ता में वापसी के बाद उल्फा के अधिकांश सदस्य इन देशों से बाहर हो गए। 2005 में, उल्फा ने शांति की उम्मीदें जगाईं, जब उसने पीछे हटने और आतंक का एक नया चरण शुरू करने के लिए 11 सदस्यीय पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप का गठन किया। 2009 में भारत में सुरक्षा बलों के जाल में फंसने के बाद, राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट के नेताओं ने सितंबर 2011 में केंद्र के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। वार्ता का विरोध करते हुए, बरुआ ने 2012 में राजखोवा को उल्फा से पैनलक्यासित कर दिया। अप्रैल में 2013 में वार्ता विरोधी समूह का नाम बदलकर उल्फा (स्वतंत्र) कर दिया गया। वार्ता समर्थक समूह ने विध्वंसक अभियानों को निलंबित करने के समझौते के 12 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

शांति समझौता क्या प्रस्ताव देता है?

समझौते के ज्ञापन के अनुसार, उल्फा हिंसा छोड़ने, निरस्त्रीकरण करने, सशस्त्र संगठन को भंग करने, अपने कब्जे वाले शिविरों को खाली करने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने पर सहमत हुआ है। अहिंसा की ओर एक बदलाव को चिह्नित करते हुए, इसका उद्देश्य उल्फा की शुरु में की गई मांग के विपरीत देश की अखंडता सुनिश्चित करना है। गृह मंत्रालय संगठन की मांगों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगा और इसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यह समझौता असम के सर्वांगीण विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले एक व्यापक पैकेज को रेखांकित करता है। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उल्फा की राजनीतिक मांगों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता है।

इनमें पूर्वोत्तर में पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से असम की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और भविष्य की परिसीमन प्रक्रियाओं में 2023 में किए गए परिसीमन अभ्यास के लिए अपनाए गए षडशानिर्देशों और पद्धति को जारी रखना शामिल है। इस समझौते में गैर-मूल निवासियों, मुख्य रूप से प्रवासी मुसलमानों को बाहर रखकर 126 सदस्यीय असम विधानसभा में स्वदेशी समुदायों के लिए अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। कहा जाता है कि 2023 के परिसीमन ने गैर-स्वदेशी समुदायों के लिए इनमें से 106 सीटों पर चुनाव लड़ना असंभव बना दिया है।

विधायी सुरक्षा के अलावा, यह समझौता असम को 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 3 से छूट देने की मांग करता है, जो उन लोगों से संबंधित है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है या जिनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है, ताकि एक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दूसरे में पंजीकृत होने से सशर्त रोका जा सके, और एक त्रुटि रहित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करें, जिसके अद्यतन पूर्ण मसौदे में 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को अस्वीकृति सूची में रखा गया था।

आगे क्या चुनौतियाँ हैं?

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद - 2016 में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 11वां - मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में 90% उग्रवाद खत्म हो गया है। संघर्ष विशेषज्ञों का कहना है कि समझौता, बशर्ते सरकार धाराओं को लागू करने का अपना इरादा दिखाए, सही दिशा में एक कदम था, लेकिन स्थायी शांति तब तक मायावी होगी जब तक बरुआ और उसके उल्फा (आई) समूह के लगभग 200 लड़ाके संघर्ष विराम पर बात नहीं करते।

उल्फा (आई) म्यांमार के सागांग डिवीजन में अपने ठिकानों से काम करता है। बरुआ, जिसे म्यांमार-चीन सीमा पर स्थित माना जाता है, ने बार-बार कहा है कि असम की संप्रभुता पर चर्चा किए बिना भारतीय कब्जे वाली ताकतों के साथ बातचीत निरर्थक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संप्रभुता पर चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि असम में कोई भी भारत से अलग नहीं होना चाहता लेकिन बरुआ को बातचीत के लिए मनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 7 अप्रैल, 1979 को उल्फा का गठन किया गया।
2. सरकार ने 1990 में ऑपरेशन बजरंग नाम से एक आक्रामक अभियान चलाया और उल्फा पर प्रतिबंध लगा दिया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to United Liberation Front of Assam (ULFA):

1. ULFA was formed on April 7, 1979.
2. The government launched an offensive called Operation Bajrang in 1990 and banned ULFA.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम कैसे अस्तित्व में आया? संगठन के साथ शांति समझौते में क्या शामिल है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम के उद्भव की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में संगठन के साथ हालिया शांति समझौते की विस्तार से चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।